भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1963
जिसका उत्तर बुधवार 2 अगस्त, 2017 को दिया जाना है

देश में इलेक्ट्रिक कारों में वृद्धि करने हेतु कदम

1963. श्री टी के रंगराजन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक कारों की संख्या में वृद्धि करने हेतु कदमों को उठाने की पहल की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कारों के उपयोग को बढ़ाने के लिए मंत्रालय कौन-कौन से प्रोत्साहन देने का विचार रखता है; और

(ग) क्या इससे कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी और यदि हां, तो इस संबंध में क्या अनुमान हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): देश में इलेक्ट्रिक कारों सहित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय ने 01 अप्रैल, 2015 से एक स्कीम नामतः फेम-इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] प्रारंभ की है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को विकासित करना तथा इसके पारिस्थितिकी-तंत्र की सहायता करना है।

इस स्कीम के तहत उद्देश्य सभी वाहन सेगमेन्टों अर्थात् दुपहिया, तिपहिया ऑटो, चौपहिया वाहनों, हल्के वाणिज्यिक वाहनों और बसों को प्रोत्साहन देकर मांग प्रोत्साहन के माध्यम से बाजार सृजन करना है। व्यापक अंगीकरण हेतु क्रेताओं (अंतिम प्रयोक्ता/उपभोक्ता) के लिए मांग प्रोत्साहन अग्रिम तौर पर घटाए गए क्रय मूल्य के रूप में उपलब्ध है।

इलेक्ट्रिक कारों सहित इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के क्रय के लिए इस स्कीम के तहत अनुमत विस्तृत मांग प्रोत्साहन का ब्यौरा फेम इंडिया स्कीम की राजपत्र अधिसूचना के **अनुबंध 13** में दिया गया है, जो भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ग): देश में इलैक्ट्रिक कारों की वृद्धि के कारण कच्चे तेल के आयात में हुई कमी पर प्रभाव का आकलन करने के लिए भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ने कोई अध्ययन नहीं किया।

******